

राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था
पंत कृषि भवन, जनपथ जयपुर-302005

क्रमांक: एफ.(78)बीप्रसं/स्टोर्स/जयपुर/2019/2163

दिनांक : 24.05.2019

बोली सूचना

संस्था द्वारा कार्यालय उपयोग हेतु कपडे की थैलियों की आपूर्ति हेतु मोहरबन्द बोलीयां आमंत्रित की जाती हैं :-

क्र. सं.	सामग्री का नाम	मात्रा	अनुमानित टेन्डर राशि रूपये	बोली दाता प्रपत्र मूल्य रूपये	बयाना राशि रूपये
1	सफेद सूती कपडे की थैली साईज 22x29 सेन्टीमीटर (सिलाई पश्चात् तैयार)	1,00,000	6,72,000/-	200/-	13,500/-
2	सफेद सूती कपडे की थैली साईज 16x24 सेन्टीमीटर (सिलाई पश्चात् तैयार)	1,00,000			

बोली की अन्य शर्तें बोली प्रपत्र में अंकित है तथा बोलीदाता प्रपत्र इस कार्यालय से कार्य समय में दिनांक 10.06.2019 दोपहर 11:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है तकनीकी बोली उसी दिन सांय 12:00 बजे तक प्राप्त कर सांय 12:30 बजे उपस्थित बोली दाताओं के समक्ष खोली जायेगी। वित्तीय बोली उन्ही बोलीदाताओं की खोली जावेगी जिनकी तकनीकी बोली सही पाई जावेगी। उक्त बोली की विस्तृत शर्तों को संस्था की वेब साइट <http://agriculture.rajasthan.gov.in/rssopca> एवं Rajasthan State Public Procurement Portal की वेबसाइट <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है।

-S/d-
(सुरेन्द्र कुमार जैन)
निदेशक

राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था,
तृतीय तल, पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर

अंतिम तिथि : 10.06.2019

तकनीकी बोली प्रपत्र

कपडे की थैलियों की आपूर्ति हेतु बोलियां।

1. वस्तुओं का नाम जिनके लिये बोली प्रस्तुत की गई है, कपडे की थैली की आपूर्ति ।
2. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक पता मय टेलीफोन / मोबाईल नंबर

3. किसको संबोधित किया गया – निदेशक, राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था, पंत कृषि भवन, जयपुर –
फोन न0. 0141-2227104, 2227315

4. संदर्भ बोली सूचना क्रमांक 2163 दिनांक 24.05.2019

5. बोली शुल्क की राशि रुपये 200/- नकद रसीद/डी0डी0संख्या
दिनांकके द्वारा जमा करा दी गई है ।

6. मैं/हम निदेशक, राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था, जयपुर द्वारा जारी की गई बोली सूचना संख्या 2163 दिनांक 24.05.2019 में वर्णित सभी शर्तों से तथा बोली प्रपत्र के साथ संलग्न की गई अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं, जिनको हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं ।

7. कपडे की थैलियों की स्पेशिफिकेशन इस प्रकार है –

क्र.सं.	सामग्री का विवरण व स्पेशिफिकेशन	मात्रा	अन्य विवरण
1.	सफेद सूती कपडे की थैली साईज 22x29 सेंटीमीटर (सिलाई पश्चात् तैयार) वजन 1450 ग्राम (100 थैली वजन)	1,00000	
2.	सफेद सूती कपडे की थैली साईज 16x24 सेंटीमीटर (सिलाई पश्चात् तैयार) वजन 850 ग्राम (100 थैली वजन)	1,00000	

8. सफेद सूती कपडे का स्पेशिफिकेशन 40x34 ENDS – PICKS PER INCH

9. सभी थैलियों के अन्दर डबल सिलाई होगी तथा खुली साईड में कपडे को मोडकर भी सिलाई करनी होगी। कपडे की थैलियों को सिंगल साईड से ग्रीन कलर में संस्था इत्यादि के नाम के मैटर सहित प्रिन्ट कर माल की आपूर्ति करनी होगी।

10. दरें एफ.ओ.आर. संस्था के जयपुर मुख्यालय स्टोर्स कार्यालय है तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु मान्य होगी तथा GST इत्यादि कर, यदि कोई हो, तो अलग से देय होगा।
11. सभी थैलियों की साईज दिये गये स्पेसिफिकेशन के अनुसार होगी।
12. माल की आपूर्ति दिये गये आदेशानुसार एक साथ दो माह में करनी होगी।
13. प्रदाय की गई सभी वस्तुएँ बोली में निर्धारित स्पेसिफिकेशन के पूर्णतया अनुरूप होगी।
14. बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्यादिनांकरूपये के लिये बयाना राशि के पेटे संलग्न किया जाता है।
15. वस्तु एवं सेवाकर पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं।
16. विनिर्माता का घोषणा पत्र भी संलग्न किया जाता है।

17. बोलीदाता की योग्यता निम्न प्रकार है :-
 1. कानूनी अस्तित्व :-
 1. बोलीदाता फर्म का पंजीयन प्रमाण।
 2. बोलीदाता के पास पेन कार्ड होना चाहिए।
 3. वस्तु एवं सेवा कर पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए।
 2. वित्तीय टर्नओवर :-
 1. बोलीदाता द्वारा गत 03 वर्षों में वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 प्रति वर्ष लगभग 15 लाख का टर्नओवर होना आवश्यक है।
 3. सेल्फ डिक्लेरेशन :- संलग्न अनुसूची 'ब'

हस्ताक्षर बोलीदाता (फर्म की मोहर)

Rajasthan State Seed & Organic Certification Agency,
3rd Floor, Pant Krishi Bhawan, Janpath, Jaipur-302005

(Financial Bid)

Name of Bidder
Address of Bidder
Mobile No.

I/We Agreed to follow the terms & conditions of bid.

I am/We are offering our rates as under for the supply of White Cloth Bag of both size :-

Sl. No.	Item Description	Quantity (Nos.)	Price Quoted per Cloth Bag Figures To be entered by the Bidder in Rs. P	GST in % (if any)	GST Amount in Rs. P	TOTAL AMOUNT With Taxes (Per Cloth Bag) in Rs. P
1	2	3	5	6	7	8
1	White Cotton Cloth Bag Size 22x29 cms	1,00000				
2	White Cotton Cloth Bag Size 16x24 cms	1,00000				

Note:-

- As per need and circumstances, the quantity of above mentioned White Cotton Cloth Bag can be changed.

Signature of the Bidder
(With Seal)

राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था, पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर

खुली बोली के लिये बोली की शर्तें एवं नियम

1. तकनीकी व वित्तीय बोली दो अलग-अलग लिफाफे में सील बन्द कर स्पष्ट रूप से लिफाफे पर लिखकर फिर एक साथ दूसरे लिफाफे में अलग से बन्द कर प्रस्तुत की जानी चाहिए। तकनीकी बिड वाले लिफाफे में निम्न दस्तावेज रखे जाने चाहिए। इन दस्तावेजों के आधार पर ही पात्रता निर्धारित की जायेगी। जो बोली दाता तकनीकी बिड में सफल पाये जायेंगे, उन्ही की वित्तीय बिड खोली जावेगी।

तकनीकी बोली के लिफाफे में रखने वाले दस्तावेजों का विवरण

1. प्रतिभूति राशि का डी.डी.-निदेशक, राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था, जयपुर के नाम से।
2. दोनो प्रकार की थैलियों का नमूना।
3. अनुसूची 'ब' में निर्माताओं द्वारा की गई घोषणा पत्र।
4. वस्तु व सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र की फोटो प्रति।
5. बोली प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर होने चाहिए।
6. आयकर विभाग द्वारा जारी पेन नं० की प्रमाणित प्रति।
7. बोली प्रपत्र नेट से डाउनलोड किये जाने पर बोली के साथ बोली प्रपत्र शुल्क रु 200/- का ड्राफ्ट निदेशक, राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था, जयपुर के नाम से।
8. वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 तक के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स/बैलेन्स सीट की सनदी लेखाकार से प्रमाणित। प्रति-स्वप्रमाणित।

नोट- उपरोक्त दस्तावेजों के अभाव में वित्तीय बोली को नहीं खोला जायेगा तथा बोली दाता द्वारा प्रस्तुत दर को शामिल नहीं किया जावेगा :-

1. एक फर्म द्वारा मात्र दोनो साईज की थैलियों के दो नमूने लगाकर अलग-अलग दर प्रस्तुत की जानी चाहिए।
2. तकनीकी बोली वाले लिफाफे में दोनो साईज की थैलियों के दो नमूने एवं डी.डी. या नकद जमा की मूल रसीद आवश्यक रूप से सलग्न की जावें जिसके अभाव में बोली पर विचार करना सम्भव नहीं होगा।
3. वित्तीय बोली वाले लिफाफे में नमूने की सिर्फ एक दर साईज के हिसाब से प्रस्तुत की जानी है इसमें केवल वित्तीय बोली प्रपत्र ही रखा जायेगा।
4. वास्तविक निर्माता/आपूर्तिकर्ता द्वारा बोली :- बोली मालों के वास्तविक निर्माता/आपूर्तिकर्ता द्वारा दी जाएगी अतः वे अनुसूची 'ब' में घोषणा प्रस्तुत करेंगे।
5. (1) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में बोलीदाता द्वारा दी जाएगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।

- (2) संविदा के सम्बन्ध में फर्म में किसी भी नये भागीदारों को बोलीदाता द्वारा फर्म में तबतक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस सम्बन्ध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते । प्राप्ति स्वीकृति के लिए बोलीदाता की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिसचार्ज) होगी ।
6. वस्तु व सेवा कर पंजीयन व शोधन प्रमाण पत्र :- कोई भी निर्माता जहाँ उसका व्यवसाय स्थित है यदि वस्तु व सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह बोली नहीं देगा । वस्तु व सेवा कर पंजीयन संख्या का उल्लेख अत्यावश्यक हैं ।
 7. बोली प्रारूप स्याही से भरा जाएगा या टंकण से भरा जाएगा । पैसिल से भरी गई किसी भी बोली पर विचार नहीं किया जाएगा । बोलीदाता बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में बोली की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा ।
 8. दरें मुख्यालय जयपुर Consignee Store होंगी ।
 9. मूल्य अधिमान: मूल्य अधिमानता राजस्थान के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों पर या राजस्थान के बाहर उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित माल की तुलना में भण्डार कय (राजस्थान के उद्योगों को अधिमानता) नियम 1995 के अनुसार दी जायेगी ।
 10. विधिमान्यता:- बोली उनके खोले जाने के दिनांक से 90 दिन तक की अवधि के लिए विधि मान्य होगी ।
 11. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सोपेगा या सबलेट पर नहीं देगा ।
 12. प्रदाय की गई सभी वस्तुएँ बोली में निर्धारित स्पेसिफिकेशन के पूर्णतया अनुरूप होंगी ।
 13. प्रदाय की जाने वाली सामग्री का विधिवत निरीक्षण क्रेता अधिकारी द्वारा नियुक्त कमेटी से किया जा सकेगा ।
 14. सप्लाई जब भी प्राप्त की जाएगी उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिये किया जाएगा कि वे स्पेसिफिकेशन के अनुरूप हैं । जहाँ आवश्यक हो वहाँ परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों में कराया जाएगा तथा जहाँ पर सप्लाई किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप विहित स्पेसिफिकेशन के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा उन्हें स्वीकार किया जाएगा ।
 15. परीक्षण प्रभार:- परीक्षण प्रभार संस्था द्वारा वहन किये जाएंगे, यदि क्रेता संस्था अपने स्तर पर परीक्षण करवाती हैं । परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात होता हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तरों या स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं है तो परीक्षण प्रभार बोली दाता द्वारा वहन किये जाएंगे ।

16. रद्द करना – निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नहीं की जाएगी उन्हें रद्द किया जाएगा तथा बोली दाता द्वारा उन्हे क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किये गये समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा।
 17. तथापि यदि संस्था कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण, पूर्ण या आंशिक रूप में उन वस्तुओं को बदलना आवश्यक नहीं समझा जाए, तो क्रेता अधिकारी बोली दाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गई कटौती अंतिम होगी।
 18. रद्द की गई वस्तुओं को बोली दाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के अंदर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे बोली दाता की जोखिम एवं उसके लेखे पर उन वस्तुओं को जिन्हें वह उचित समझे, बेचने का अधिकार होगा।
 19. बोली दाता उचित पैकिंग करने के लिये उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके किसी प्रकार की हानि, क्षति या किसी कमी के होने के मामले में, बोली दाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जाँच निरीक्षण किये जाने पर पाई गई ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिये उत्तरदायी होगा। इसके लिये कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी।
 20. प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल की सप्लाई क्रेता अधिकारी को संतुष्टि के अनुसार नहीं की जाती हैं तो बोली दातादाता को सुनवाई का एक अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।
 21. बोली दाता को उसके प्रतिनिधि की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।
1. सुपुर्दगी अवधि: बोली दाता जिसकी बोली स्वीकार की जाएगी वह सप्लाई आदेशों के अनुसार निश्चित अवधि के भीतर सामान की सप्लाई करने की व्यवस्था करेगा।
 2. मात्रा की सीमा:— आदेश को फिर से देना: यदि बोली दाता सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिये आदेश दिया जाता है तो बोली दाता अपेक्षित सप्लाई की पूर्ति करने केलिये बाध्य होगा। पुनः आदेश भी बोली में दी गई शर्तों पर दिये जा सकेंगे, परंतु शर्त यह है कि ऐसे पुनरादेश मुल रूप में खरीदी गई मात्रा को 50 प्रतिशत तक की सप्लाई के लिये ही होंगे। तथा ऐसे आदेश देने की अवधि अंतिम माल प्रदाय करने के दिनांक से एक माह से अधिक बाद की नहीं होगी यदि बोली दाता, ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता है तो क्रेता अधिकारी अवशेष सामान की सप्लाई की व्यवस्था सीमित बोली द्वारा या अन्यथा प्रकार से करने के लिये स्वतंत्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जाएगी उसकी बोली दाता से वसूली की जाएगी।

3. यदि क्रेता अधिकारी किन्ही निवेदित वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या बोली प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है तो बोली दाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिये अधिकृत नहीं होगा।

23. बोली प्रतिभूति राशि :-

(क) तकनीकी बोली के साथ बयाना राशि नियमानुसार प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना बोली पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक प्रामाणीकरण संस्था, जयपुर के पक्ष में निम्नलिखित में से किसी भी रूप में जमा कराई जानी चाहिये।

1. शिडयूअल बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक

(ख) बोली प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय :- असफल बोली दाता को बोली प्रतिभूति राशि बोली दाता को अंतिम रूप से स्वीकार करने के बाद शीघ्र लौटाई जाएगी।

(ग) बोली प्रतिभूति राशि से छूट - बोली प्रतिभूति राशि लघु उद्योगों के लिए उनके द्वारा प्रस्तावित मात्रा के मूल्य का 1/2 प्रतिशत राशि होगी, रूग्ण इकाईयों के लिए यह राशि 1 प्रतिशत एवं अन्य के लिए बयाना राशि अनुमानित मूल्य के 2 प्रतिशत मूल्य के बराबर होगी। उन फर्मों को, जो निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास पंजीकृत है उन मदों के सम्बन्ध में जिनके लिए वे उक्त रूप में रजिस्टर्ड की गई है उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण पत्र या उसकी फोटोस्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर, उनके द्वारा प्रस्तावित मात्रा के मूल्य के 1/2 प्रतिशत की दर पर बयाना राशि जमा करानी होगी

(घ) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बोली प्रतिभूति राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। यदि वे स्वयं द्वारा उत्पादित माल की बोली देते हैं।

(ङ) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गई या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बोली प्रतिभूति राशि/प्रतिभूति निक्षेप को नयी बोली के लिये बयाना राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा यथापि यदि बोली को पुनः आमंत्रित किया जाता है तो बयाना राशि को उपयोग में लिया जा सकता है।

24. बोली प्रतिभूति राशि का समपहरण: बोली प्रतिभूति राशि को निम्न मामलों में समपृहृत कर लिया जाएगा :-

1. जब बोली दाता बोली खोलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें उपान्तरण करता है।
2. जब बोली दाता प्रदायगी के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हो।

3. जब बोली दाता विहित समय के भीतर सप्लाई आदेश के अनुसार मदों की आपूर्ति प्रारंभ करने में असफल रहता हो।
25. (1) करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप:-
1. सफल बोली दाता को बोली स्वीकार करने की सूचना प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों के लिये बोली स्वीकार की गई है उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा करानी होगी यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको बोली के स्वीकार किये जाने की सूचना उसे दी गई है, 7 दिन के भीतर जमा कराई जाएगी।
 2. लघु उद्योगों के लिए उनके द्वारा आदिष्ट मात्रा का 1 प्रतिशत एवं रूग्ण इकाई के लिए 2 प्रतिशत होगी, अन्य के लिए अनुमानित मूल्य का 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि देय होगी।
 3. राज्य के बाहर की कोई विनिर्माता की दर न्यूनतम आती है तो वित्त विभाग के आदेश दिनांक 30.01.99 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसके अनुसार राज्य की फर्म को प्राथमिकता दी जायेगी व 20 प्रतिशत राज्य के बाहर की न्यूनतम दर दाता को आपूर्ति आदेश दिये जायें एवं 80 प्रतिशत राज्य के न्यूनतम दर दाता को आदेश दिये जायेंगे।
 4. बोली के समय जमा कराई गई प्रतिभूति राशि को कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि के लिये समायोजित किया जाएगा। कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में प्रतिभूति राशि से कम नहीं होगी।
 1. बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक
 2. डाकघर बचत बैंक पास बुक्स जिसे विधिवत गिरवी रखा जाएगा।
 3. अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिये राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत पत्र व डिफेन्स सेविंग प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र या कोई अन्य स्क्रिप्ट / विलेख यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता है। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार किया जाएगा।
 5. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा व्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
 6. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे।
 7. एक समय खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार मदों की अंतिम सप्लाई से एक माहके भीतर तथा यदि सुपुर्दगी को सान्तर किया जाता है तो दो माह के भीतर उसके लिये सविदा के संतोषजनक रूप से पूर्ण किये जाने के बाद या गारंटी की अवधि, यदि हो, के समाप्त हो जाने के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे संतुष्ट हो जाने पर कि बोली दातादाता के विरुद्ध कोई देय बकाया नहीं है, प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।

8. कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण:- प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहत किया जाएगा:
- (क) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
 - (ख) जब बोली दाता सम्पूर्ण सप्लाई संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
 - (ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहत करने के मामलों में युक्ति युक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
 - (घ) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टॉप लगाने का व्यय बोली दाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टॉपशुदा प्रतिपडत निःशुल्क प्रस्तुत की जाएगी।

26. बीमा :-

1. सामान गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किये जाएंगे यदि सप्लायर चाहे तो वह मूल्यवान सामान को चोरी, नाश या क्षय द्वारा या आग, बाढ , मौसम में पडा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे युद्ध, विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार बोली दाताद्वारा वहन किया जाएगा तथा यदि ऐसे व्यय किये जाते हैं तो राज्य से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
2. यदि क्रेता द्वारा चाहा गया हो तो क्रेता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जाएगा। ऐसे मामलों में बीमा सदैव भारतीय बीमा निगम या उसकी सहायक शाखाओं से कराया जाना चाहिए।

27. भुगतान :-

1. संस्था द्वारा किसी भी स्थिति में अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
2. जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान बोली दाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार बोली दाता द्वारा वहन किये जाएंगे।
3. विवादास्पद मदों के संबंध में, राशि के 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।
4. उन मामलों के संबंध में जिनमें परीक्षण करने के जरूरत हैं, भुगतान तभी किया जाएगा जब वे परीक्षण कर लिये जाएंगे तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित स्पेसीफिकेशन के अनुसार होंगे।
5. बोली प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल बोली दाता क्रेता अधिकारी से फर्म आर्डर के प्राप्त होने से अवधि के भीतर सप्लाई करेगा।

28. परिनिर्धारित क्षति:- परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामलों में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिये की जाएगी जिनकी बोली दाता सप्लाई करने में असफल रहा है :-
- (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलंब के लिए 2½ %
 (ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनाधिक के लिए 5 %
 (ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनाधिक अवधि के लिए 7½ %
 (घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलंब के लिए 10 %
 (ङ) विलंब की अवधि में आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा ।
 (च) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी ।
 (छ) यदि प्रदायकर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसमें प्रदायगी हेतु आवेदन दिया है। किन्तु वह उसके लिये निवेदन बाधा के घटित होने के तुरंत बाद करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा ।
29. वसूलियाँ :- परिनिर्धारित क्षयों, कम सप्लाई, टूटफूट, रद्द की गई वस्तुओं के लिये वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी । कम सप्लाई, टूट फूट व रद्द किये गये मालों की सीमा तक राशि को भी रोकी जा सकेगी तथा सप्लायर संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षय के साथ वसूली उसको देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी । यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पीडीआर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी ।
30. बोली दाताओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी चाहिए ।
31. यदि बोली दाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो उसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है तो उसकी बोली दाता को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही को रद्द कर दिया जाएगा किसी भी सुरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये बोली स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लिखित न किया गया हो ।
32. क्रेता अधिकारी किसी भी बोली को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली दाता नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बताये किसी भी बोली को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए बोली दाता ने बोली दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए बोली दाता को स्वीकार करने या एक फर्म / सप्लायर से अधिक को स्टोर्स की मदो को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा ।

33. बोली दाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :-
1. यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख की एक प्रमाणित प्रति
 2. यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार आफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष
 3. एक मात्र स्वामित्व के मामलें में आवास, एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नंबर, कंपनी के मामलें में कंपनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र
34. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामलें को विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा जो उस विवाद के लिये एक मात्र मध्यस्थ के रूप में आने वाले अपने वरिष्ठतम उप अधिकारी की नियुक्ती करेगा यह उप अधिकारी इस संविदा से संबंध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा ।
35. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भीपक्षकार द्वारा (संस्था या ठेकेदार) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी। अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी ।
36. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त जहां आवश्यक हो राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 के प्रावधान लागू होंगे ।

बोली दातादाता के हस्ताक्षर

Annexure -B

I/We declare I am/we are bonafide Manufacturers in the Goods for which I/We have tendered.

If this declaration is found to be incorrect then without prejudice to an other action that may be taken my/our security may be forfeitted in full and the tender if any to the extent accepted may be cancelled.

Signature of the tenderer

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

- a. have controlling partners/ shareholders in common; or
- b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
- d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of in response to their Notice Inviting Bids No..... Dated..... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:

Place:

Signature of bidder

Name :

Designation:

Address:

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is _____

The designation and address of the Second Appellate Authority is _____

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procurement;
- (b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

Doc1

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal Noof

Before the (First / Second Appellate Authority)

I. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

.....
.....
..... (Supported by an affidavit)

7. Prayer:

.....
.....

Place

Date

Appellant's Signature

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.